

वर्तमान समय में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के आसपास है जो दिल्ली की तरह 400 के पार जाना तय

वायु प्रदूषण को नहीं रोक पाई सरकार पराली की आग भी नियंत्रण से बाहर

हकीकत: निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर, सड़कें भी खराब

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

वातावरण में पहले से धूल जानलेवा बनी हुई थी अब खेतों में पराली जलाने के लिए लगाई जा रही आग ने वायु प्रदूषण को और गति दे दी है। मग्न तो मग्न, लेकिन इसकी लपटें दिल्ली तक पहुंच रही हैं। वायु प्रदूषण वाले पूरे माहौल से लोग परेशान हैं। यह स्थिति आगे और बिगड़ने वाली है। अभी हवा में वायु प्रदूषण की स्थिति बताने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के आसपास है जो दिल्ली की तरह 400 के पार जाना तय है। इस पर राजनीतिक सियासत भी शुरू हो गई है। आप सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण को वजह मग्न में पराली जलाने की घटनाओं को बताया है।



मग्न में इस समय युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, इनमें से 95 फीसद खुले में हो रहे हैं, जिनकी वजह से धूल वातावरण में फैली हुई है। दूसरी ओर सड़कें खराब हैं, जिन पर दौड़ रहे वाहनों के कारण भी वातावरण में धूल का माहौल है। उपर से टंड का सीजन शुरू हो चुका है, जिसमें नमी है। विशेषज्ञों के मुताबिक नमी के कारण धूल के कण भारी हो रहे हैं जो निचले

वातावरण में रहते हैं इसलिए वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। आमतौर पर यह स्थिति गर्मी में भी रहती है लेकिन उस समय मौसम पूरी तरह शुष्क रहता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण का अहसास नहीं होता।

पराली जलाने से खेतों को नुकसान

पराली जलाने के कारण खेतों की मिट्टी बर्बाद हो रही है, उर्वरा शक्ति पर विपरीत असर पड़ा है। आसपास की वनस्पतियां बर्बाद हुई हैं। कीट-पतंगों की वातावरण में कमी होने लगी है। किसान यह बात समझ रहे हैं, उन्हें यह भी पता है कि पराली जलाते रहे तो नई मिट्टी बनने की प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी। मग्न के नर्मदापुरम, बैतूल, भोपाल, हरदा, छतरपुर समेत कई किसानों ने पराली जलाना बंद कर दिया है। वह फसल की कटाई नीचे से कर रहे हैं ताकि खेतों में फसल के तने न छूटे। आमतौर पर तने छूट जाने के कारण कई बार नई फसल की बुवाई करने में दिक्कत होती है।

भाजपा नेता वीडी शर्मा ने दिल्ली सीएम से कहा- मग्न आ जाएं



वहीं इस मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने खुलकर आरोप लगाए कि वहां पराली जलाने के कारण दिल्ली की आबोहवा बिगड़ी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि यहां की हवा दिल्ली की तुलना में कई गुना अच्छी है यदि आतिशी को अच्छी हवा में सांस लेनी हो तो वे मग्न आ जाएं।

10 हाथियों की मौत होने के बाद बांधवगढ़ के वन्य प्राणी डॉक्टर को हटाया भोपाल। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के 22 दिन बाद वन्यप्राणी डॉक्टर नितिन गुप्ता को भी हटा दिया है। इसके पहले रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर गौरव चौधरी और एसडीओ निनामा को हटाया गया था। पूर्व के दो अधिकारियों को निलंबित किया गया था। डॉ. गुप्ता को केवल रिजर्व से हटाकर मुकुंदपुर भेजा गया है। उनकी जगह मुकुंदपुर सतना से वन्यप्राणी डॉ. राजेश तोमर को पदस्थ किया है। रिजर्व में 29 से 31 अक्टूबर के बीच 10 हाथी बीमार हो गए थे। जिनकी मौत हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ के इलाज में देरी हुई थी। इसकी वजह वन्यप्राणी डॉक्टर द्वारा समय रहते इलाज शुरू नहीं कर पाना बताया जा रहा है। जांच टीमों की जानकारी में आया कि डॉ. गुप्ता उस दौरान बाहर थे, सूचना के बावजूद भी जल्द नहीं पहुंचे थे हालांकि संबंधित अधिकारी ये आरोप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कई अधिकारी निशाने पर: हाथी की मौत मामले में और भी कई अधिकारी निशाने पर बताए जा रहे हैं। इनमें डिप्टी डायरेक्टर, कुछ एसडीओ, रेंजर व मैदानी अमला शामिल है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कमियों से जड़ी लगातार खबरें आ रही हैं लेकिन प्रबंधन कारवाही करने में महज खानापूरी कर रहा है।

राज्यमंत्री पटेल की फटकार संग्रहण क्षमता और मार्केटिंग में क्यों कमजोर?

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के राज्यमंत्री लखन पटेल ने सहकारी दुग्ध संघों की कमजोर स्थिति पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। पूछा कि संग्रहण क्षमता और मार्केटिंग में क्यों पिछड़े।





राज्यमंत्री लखन पटेल ने सहकारी दुग्ध संघों के कार्यों की समीक्षा की

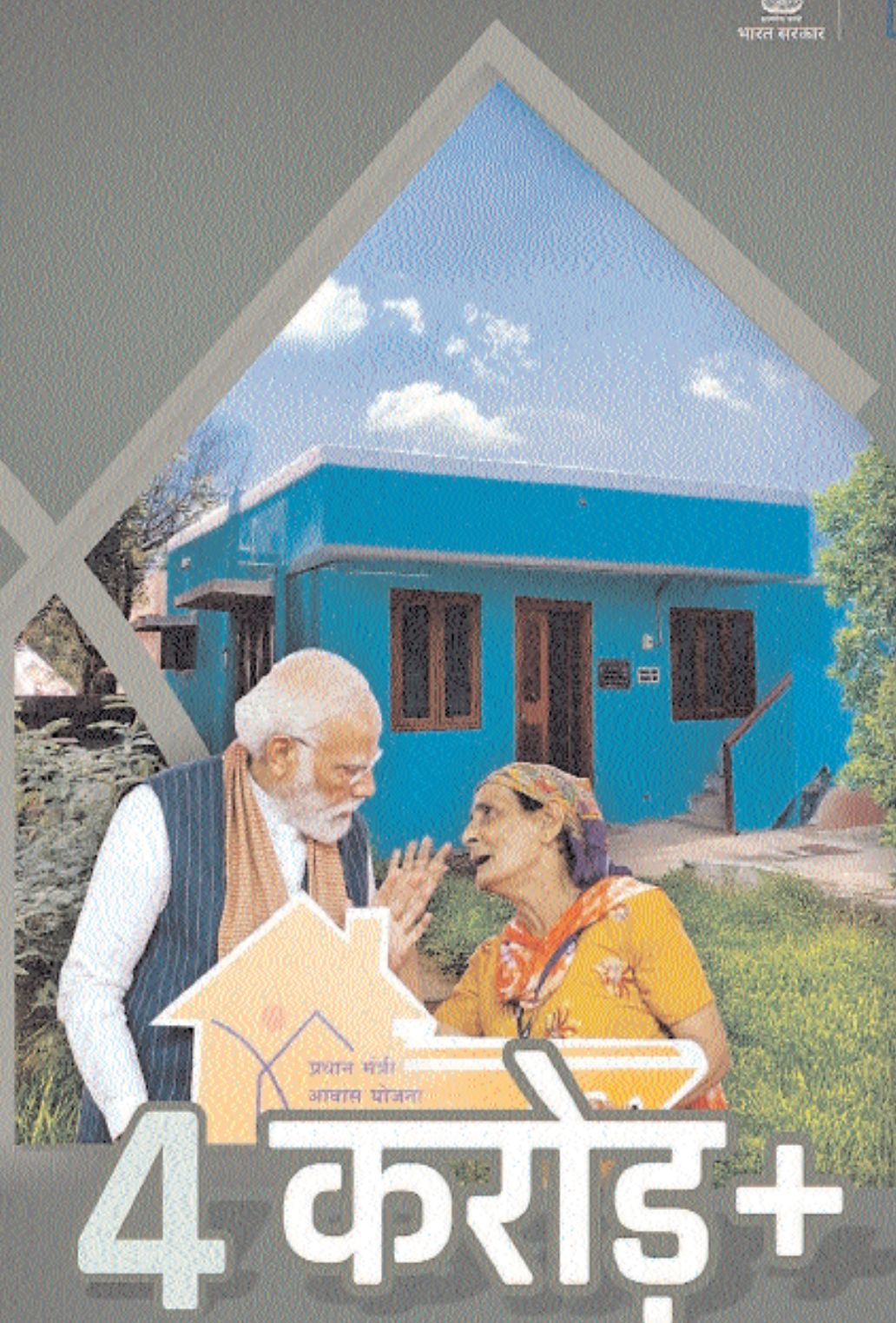
अधिकारियों के पास जवाब नहीं थे, कई तो एक-दूसरे का मुंह देखने लगे। राज्यमंत्री ने फिर कहा, ऐसा नहीं चलेगा। कमियां पूरी करो और नया प्लान लेकर आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं।

राज्यमंत्री पटेल ने मंगलवार को दुग्ध संघों के कार्यों की समीक्षा की थी। असल में कहने को तो मग्न के सहकारी दुग्ध संघ 35 साल पुराने हैं लेकिन इन संघों से नई-नई निजी कंपनियां आगे निकल गईं, जो कि बाद में मग्न आई थी और ये कमजोर प्रबंधन के कारण जहां के वहां रह गए। जबकि केंद्र व राज्य ने इन पर जमकर रुपये लूटाए थे। अब मोहन सरकार इन सहकारी दुग्ध संघों को आम नागरिकों, युवाओं और किसानों के लिए उपयोगी बनाने के लिए जुटी है। जिसका मकसद नागरिकों को सस्ता दूध, युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार व स्वरोजगार और किसानों को दुग्ध उत्पादन में लाभ दिलाना है। ये सहकारी दुग्ध संघ दूध के संग्रहण, प्रोसेसिंग, विपणन से जुड़े कार्यों में बहुत पीछे हैं। मंत्री ने बताया कि समीक्षा में उन्होंने इन्हें विषयों पर जोर दिया। यह भी कहा कि जो सहकारी दुग्ध संघ घाटे में हैं, उन्हें फायदे में लाने के प्रयास तेज कीजिए। बैठक में प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव, एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के अधिकारी व सभी सहकारी दुग्ध संघों के सीईओ मौजूद थे। मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि जिला अस्पतालों, कलेक्टर कार्यालयों समेत नागरिकों के आवागमन से जुड़े सरकारी कार्यालयों में सहकारी दुग्ध विक्रय बूथ खोले। इनके जरिए दूध व उससे बने उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दें। महिला स्व-सहायता समूह को सहकारी दुग्ध संघों से जोड़ा जाए, दुग्ध उत्पाद केंद्रों के लिए बनाए बूथों को आकर्षक बनाएं। दुग्ध से बने अन्य उत्पादों की संख्या बढ़ाएं, नए रूट तलाशें, ऐसे शहरों व कस्बों तक जाएं, यहां सहकारी सेक्टर कमजोर है। प्रभावी विपणन तकनीक का उपयोग करें। आगामी 1 वर्ष के लिए कार्य-योजना बनाकर काम शुरू करें।

ग्रामीण विकास उत्सव, उत्पादों और कारीगरों के प्रोत्साहन का प्रभावी मंच: राज्यपाल

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि ग्रामीण विकास उत्सव, देश भर के कारीगरों और प्रसिद्ध उत्पादों के प्रोत्साहन का प्रभावी मंच है। ऐसे आयोजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ महिला सर्वाधिकारण की दिशा में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। राज्यपाल श्री पटेल नाबार्ड द्वारा भोपाल हॉट बाजार में आयोजित ग्रामीण विकास उत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 19 से 27 नवम्बर तक आयोजित हो रहे ग्रामीण विकास उत्सव का फीता काटकर शुभारंभ किया। राज्यपाल श्री पटेल ने विगत 6 वर्षों से देशभर के कारीगरों के प्रोत्साहन के लिए उत्सव का आयोजन करने पर नाबार्ड को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ऐसे आयोजनों का व्यापक और सघन स्तर पर प्रचार-प्रसार करें। राज्यपाल श्री पटेल ने स्थानीय मीडिया से भी अपील की कि देश के कारीगरों के उत्पादों के प्रचार-प्रसार में भरपूर सहयोग करें।



प्रधानमंत्री आवास योजना

4 करोड़+

परिवारों को सुरक्षा, सुविधा और स्वाभिमान

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत

अब तक बने 4 करोड़ से अधिक पक्के घरों से करोड़ों लोगों को गरिमापूर्ण जीवन मिला है। इन बढ़िया क्वालिटी के आवासों में गैस, बिजली, पानी जैसी सभी सुविधाएं हैं। इससे लोगों को बीमारियों एवं कई तरह की कठिनाइयों से मुक्ति मिली है। वे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें आजीविका के नए अवसर मिल रहे हैं। उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। महिलाएं सशक्त हुई हैं, क्योंकि आज 73% घर महिलाओं के नाम पर हैं। प्रधानमंत्री आवास के ये घर प्रदेश की संस्कृति और वहां की विविधता के प्रतीक भी हैं।

₹5.36 लाख करोड़ की सहायता से 3 करोड़ और परिवारों को मिलेगा अपना पक्का घर

cbc 44101113000112425

